तेल के दामों में कटौती से नहीं बिगड़ेगा राजकोषीय संतुलन

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। पेट्रोल व डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को राहत देने के सरकार के फैसले से राजकोषीय संतुलन नहीं बिगड़ेगा। सरकार का कहना है कि पेट्रोल व डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में डेढ़ रुपये प्रति लीटर की कटौती से सरकारी खजाने पर मात्र 10,500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा जो चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का मात्र का 0.05 प्रतिशत है। हालांकि केंद्र ने जनता को राहत देने का जो फॉर्मूला अपनाया है, उससे सरकारी तेल कंपनियों की सेहत पर असर पड़ना तय है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद सरकार राजकोषीय घाटे को काबू रखने में कामयाब रहेगी। सरकार पहले ही उधार लेने की अपनी योजना में 70,000 करोड़ रुपये की कटौती कर चुकी है। इसके अलावा तेल कंपनियों को विदेश से 10 अरब डॉलर राशि उधार लेने संबंधी छूट भी दी है। उन्होंने कहा कि जब पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी तो उपभोक्ता अन्य चीजों पर खर्च कर सकेंगे जिससे मांग बढ़ेगी।

जेटली ने साफ कहा कि उनकी सरकार टैक्स रेट बढ़ाकर नहीं बल्कि टैक्स बेस बढ़ाकर खजाना भरने में यकीन रखती है। उनका इशारा नोटबंदी और जीएसटी के बाद प्रत्यक्ष व परोक्ष करदाताओं की संख्या में वृद्धि की ओर था।

राजस्व प्राप्तियों व ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार का बजट 24.42 लाख करोड़ रुपये का है और इसमें राजकोषीय घाटा 6.24 लाख करोड़ यानी 3.3 प्रतिशत है। इस हिसाब से पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के फैसले का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा।

सरकार नवंबर 2014 से लेकर अब तक पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नौ बार बढ़ा चुकी है जबकि कटौती सिर्फ एक बार ही की है। पिछले साल सरकार ने अक्टूबर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया था। अब पुनः कटौती का फैसला किया गया है। यही वजह है कि सरकार केंद्रीय करों में राज्यों को 42 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के बावजूद अपना राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में कामयाब रही है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार को पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जरिये 2.28 लाख करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आए थे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 43 हजार करोड़ रुपये पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार के खजाने में आ चुके हैं। हालांकि जेटली ने स्वीकार किया कि चालू खाते के घाटे को काबू रखने की चुनौतियां बरकरार हैं। सरकार गैर-जरूरी आयातों को कम करने तथा भारतीय कंपनियों को मसाला बांड जारी कर विदेश से पूंजी जुटाने की अनुमति देने जैसे निर्णय कर चुकी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने जो फॉर्मूला अपनाया है, उसका असर तेल कंपनियों की सेहत पर पड़ना तय है। दरअसल तेल कंपनियों को एक रुपया प्रति लीटर के हिसाब से कीमत कम करनी पड़ेगी। ऐसे में उन पर बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने जैसे ही यह घोषणा की बाजार पर इसका असर दिखा।

शेयर बाजार में तेल कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनी एचपीसीएल का शेयर 12.23 प्रतिशत गिरकर 220.60 रुपये पर बंद हुआ जबकि बीपीसीएल के शेयर में भी 10.89 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 336.35 रुपये पर बंद हुआ। इसी तरह इंडियन ऑयल के शेयर में 10.57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 140.85 रुपये पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप व कैपिटल मार्केट स्ट्रैटजी प्रमुख वीके शर्मा का कहना है कि तेल कंपनियों पर एक रुपया प्रति लीटर का बोझ पड़ने से उनके लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 85 डालर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। कच्चे तेल का यह भाव बीते चार साल में सर्वाधिक है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से कीमतें घटाने की मांग की है।

निवेशकों की पहली पसंद बने म्युचुअल फंड, 14%बढ़ा निवेश

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। म्युचुअल फंड लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में म्युचुअल फंड एसेट 14 फीसद बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ना है। उद्योगों की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का भी फायदा हुआ है। पिछले साल इस दौरान यह रकम 21 लाख करोड़ रुपये थी। बता दें कि फिलहाल म्युचुअल फंड उद्योग में कुल 41 कंपनियां हैं। इनके पास जून-अगस्त तिमाही में 23.4 लाख करोड़ रुपये थे। विशेषज्ञों का मानना है इस बढ़ोतरी के पीछे खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी है। साथ ही इंडस्ट्री की तरफ से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से छोटे शहरों में म्युचुअल फंड को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। इस वजह से सिस्टैमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान (सिप) में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वजह से म्युचुअल फंड हाउस के एयूएम में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है और यह खुदरा निवेशकों की पहली पसंद बन रहे हैं। नियमित अंतराल पर छोटी-छोटी रकम जमा करने के ऑप्शन के कारण खुदरा निवेशक इसमें अच्छा निवेश कर रहे हैं. म्युचुअल फंड उद्योग की 41 कंपनियों में 33 के एयूएम में समीक्षाधीन अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है। जबकि सालाना आधार पर बाकी आठ कंपनियों के एयूएम में गिरावट आई है। इस मामले में सबसे आगे आईसीआईसीआई फ्रूडेंशियल म्युचुअल फंड है। पिछले महीने समाप्त हुई तिमाही में इसके एयूएम 3,10,257 करोड़ रुपये पर थे। आईसीआईसीआई के बाद एचडीएफसी (3,06,360 करोड़ रुपये) और आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड (2,54,207 करोड़ रुपये) का नंबर आता है। चौथे स्थान पर एसबीआई म्युचुअल फंड (2,53,829 करोड़ रुपये) है। इसने रिलायंस म्युचुअल फंड की जगह ली है। रिलायंस म्युचुअल फंड के एयूएम 2,40,445 करोड़ रुपये पर हैं। यह पहले चौथे स्थान पर था।

फोर्ड ने बाजार में उतारी अपडेटेड कॉम्पैक्ट सेडान एस्पायर

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। फोर्ड इंडिया ने अपनी नई अपडेटेड कॉम्पैक्ट सेडान एस्पायर को बाजार में उतारा है। एस्पायर का शुरुआती पेट्रोल मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 5.55 लाख रुपये रखी गई है। जबकि डीजल की कीमत 6.45 लाख रुपये होगी। फोर्ड इंडिया के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने बताया कि पेट्रोल के मैनुअल वर्जन के विभिन्न मॉडलों की कीमत 5.55 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक रखी गई है। जबकि पेट्रोल के ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 8.49 लाख रुपये रखी गई है। डीजल चालित नई एस्पायर की कीमत 6.45 से 8.14 लाख रुपये (एक्स शोरूम) रखी गई है। मेहरोत्रा ने कहा कि कंपनी का प्रयास है कि एस्पायर के जरिये ग्राहकों को वह सब मिले जो वे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कॉम्पैक्ट सेडान का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इस साल के अंत तक इसके 4.5 लाख यूनिट तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस दशक के अंत तक इसके दोगुना हो जाने की उम्मीद है। मेहरोत्रा ने कहा कि फोर्ड ने अपनी कारों में घरेलू कलपुर्जों के इस्तेमाल का अनुपात बढ़ाकर 85 फीसद कर लिया है। साल 2017-18 में कंपनी की कारों की घरेलू बिक्री एक अरब डॉलर को पार कर चुकी है। जबकि निर्यात से कंपनी को इस अवधि में 2.4 अरब डॉलर का रेवेन्यू मिला है।

मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया वैगन आर का नया अवतार

नयी दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपनी कॉम्पैक्ट हैचबैक वैगन आर का सीमित संस्करण पेश किया है. इसके साथ दो वैकल्पिक एक्सेसरीज किट का विकल्प दिया गया है जिसकी कीमत 15,490 और 25,490 रुपये है. वैगन आर सीमित संस्करण के साथ कई अतिरिक्त फीचर्स मसलन रिवर्स पार्किंग सेंसर आदि दिये गये हैं. मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (एमएंडएस) आर एस कल्सी ने कहा, वैगन आर के ग्राहकों के लिए हम इस त्योहारी सीजन को और शानदार बनाना चाहते हैं. वैगन आर देश की पांच सबसे अधिक बिकने वाली कारों में है. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर की अवधि में कंपनी ने इसकी 85,000 से अधिक इकाइयां बेची हैं. इस कार को 1999 में पेश किया गया था. उसके बाद से कंपनी इसकी 21.9 लाख इकाइयां बेच चुकी है.

केनरा बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के प्रमुख नियुक्त

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। सरकार ने शुक्रवार को केनरा बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। सूत्रों ने बताया कि शर्मा को छह माह की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बी श्रीराम को तीन माह के लिए आईडीबीआई बैंक का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल सितंबर, 2018 में पूरा हो गया। यह नियुक्ति इसके बाद की गई है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि शर्मा के पास बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अगुवाई करने का अनुभव है। केनरा बैंक में आने से पहले शर्मा लक्ष्मी विलास बैंक के प्रमुख थे। केनरा बैंक में उनका तीन साल का कार्यकाल जुलाई, 2018 में पूरा हुआ था।

आईएलएफएस को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकार मदद करने को तैयारः गडकरी

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)।। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) के नए प्रबंधन के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पुनरोद्धार के बारे में सुझावों को सुनने को तैयार है। गडकरी ने यहां भारत-रूस व्यापार शिखर बैठक के मौके पर अलग से बातचीत में कहा, ''हमारा काम सड़क परियोजनाओं को रोकना नहीं है। हमारा काम नियम और नियमनों के तहत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। यदि कोई कंपनी या ठेकेदार किसी दिक्कत का सामना कर रहा है तो हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे।''

अधिकतर भारतीय एफटीए वार्ताओं में रक्षात्मक रुख चाहते हैंः सुरेश प्रभु

नयी दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अधिकतर उद्योग संघ चाहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ताओं में रक्षा रुख अपनाया जाए और सीमा शुल्क में की जाए। प्रभु ने भारत-चीन व्यापार पर वाणिज्य विभाग की ओर से किये गए एक अध्ययन को जारी करने के मौके पर यह बात कही। विभाग ने प्रभु के हवाले से कहा है, अधिकतर उद्योग संघ चाहते हैं कि सरकार एफटीए पर रक्षात्मक रुख अपनाते हुए आगे बढ़े और घरेलू उत्पादकों के लिए घरेलू बाजार के सिद्धांत के आधार पर शुल्क में वृद्धि करे।

मोबाइल-बैंक अकाउंट से आधार लिंक बहाल किया जा सकता है : जेटली

नई दिल्ली ,06 अक्टूबर (ए)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पास कानून के जरिए मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट से आधार लिंकिंग को बहाल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार ऐसा कानून लाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी थी। हालांकि, 12 डिजिट वाले बायोमीट्रिक नंबर से पहचान सत्यापन से टेलिकॉम ऑपरेटर्स और निजी कंपनियों को रोक दिया था।

जेटली ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, कोर्ट ने यह स्वीकार किया है आधार के पीछे वैध उद्देश्य है। आधार नागरिकता का कार्ड नहीं है। हमारे यहां सिस्टम है कि मदद और सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी राशि सरकार लोगों के बीच बांटती है। आधार के पीछे यह एक मुख्य उद्देश्य था। जेटली ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां भी आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कानून बनाना होगा। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए सेक्शन 57 का हवाला दिया।

वित्त मंत्री ने कहा, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून के सही प्रविजन का इस्तेमाल करना होगा, किसी भी क्षेत्र में इसकी जरूरत महसूस की जाए। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि सरकार मोबाइल और बैंक अकाउंट से आधार लिंकिंग के लिए कानून लाएगी या नहीं। जेटली ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुपातिक आधार पर इनकम टैक्स समेत कई क्षेत्रों में आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी है।

अगर टेलिकॉम कंपनियां इसी तरह डेटा के आधार पर लिंकिंग (आधार लिंकिंग) को जरूरी साबित कर दे तो ऐसा संभव है। इसलिए आधार लिंकिंग के लिए मोबाइल और बैंक 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

ई-वे बिल के लिए जरूरी हुआ पिन कोड

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (ए)। कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को अब ई-वे बिल जनरेट करते वक्त माल की लोडिंग और अनलोडिंग प्वाइंट के अलावा उन स्थानों का पिन कोड भी डालना होगा। इस कदम का मकसद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संभावित चोरी को रोकना है। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के अधिकारियों ने कहा कि पिन कोड का उल्लेख करने से माल की लोडिंग और अनलोडिंग प्वाइंट के बीच की वास्तविक दूरी का पता चल जाएगा। इसके साथ ही पिन कोड से बिल की वैधता भी नहीं छुपाई जा सकेगी। अब तक कारोबारियों को ई-वे बिल जनरेट करते वक्त सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग प्वाइंट और उनके बीच की दूरी का ही जिक्र करना होता था।

अधिकारियों ने कहा कि ई-वे बिल की वैधता दोनों स्थानों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ऐसे में एक ही ई-वे बिल पर कई चक्कर लगाने और कर-चोरी करने का अंदेशा था। वर्तमान में 100 किमी से कम दूरी के लिए ई-वे बिल की वैधता एक दिन की होती है। उसके बाद हर 100 किमी के लिए बिल की वैधता एक दिन बढ़ जाती है।

इस नए नियम के साथ जीएसटीएन ने कारोबारियों को एक नई सुविधा भी दी है। इसके तहत ई-वे बिल जनरेट करते वक्त अगर कारोबारियों द्वारा दर्ज किया गया इनवॉयस मूल्य बहुत ज्यादा होगा, तो उन्हें एसएमएस के माध्यम से अलर्ट किया जाएगा। इससे वे सुनिश्चित हो पाएंगे कि गलती से मूल्य ज्यादा नहीं दर्ज कर दिया गया है। जीएसटीएन ने कहा कि वह ई-वे बिल व्यवस्था को बेहद सरल बनाने की सतत कोशिशों के तहत नए फीचर जोड़ रही है।

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर

भारी छूट देने वाली कंपनियों पर होगी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली ,06 अक्टूबर (ए)। ऑनलाइन सामान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब आपको ऑनलाइन सामान खरीदने पर भारी छूट नहीं मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा वस्तुओं के दाम बढ़ा-चढ़ा कर उन पर भारी छूट देने की कवायद पर लगाम लगाने की तैयारी में है।

अगर कोई ऑनलाइन कंपनी अधिकतम खुदरा मूल्य से छेड़छाड़ करती है तो इसे व्यावसायिक धोखाधड़ी माना जाएगा, जिसके तहत उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मंत्रालय ने ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देश तैयार कर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को भेज दिए है, इन दिशा-निर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी, धोखाधड़ी और ठगी से ग्राहकों को बचाने के उपाय शामिल है।

मंत्रालय ने डीआईपीपी को हाल ही में ई-कॉमर्स से जुड़े जो दिशा-निर्देश भेजे हैं, उनमें उत्पाद पहुंचाने, उत्पाद वापसी, पैसा वापसी और बदलाव को पारदर्शी बनाने संबंधी नियम शामिल हैं। इन निर्देशों को तैयार करने में मंत्रालय ने क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों को भी शामिल किया है। साथ ही इसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट करना अनिवार्य किया गया है और एमआरपी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और फिर उसमें छूट दिखाने का चलन अब नहीं चलेगा। ऐसा करने को व्यावसायिक धोखाधड़ी माना जाएगा।

हीरे पर आयात शुल्क बढ़ने पर कारोबार 60 फीसदी तक घटने की आशंका

मुंबई, 6 अक्टूबर (ए)। सरकार की तरफ से कट-पॉलिश्ड हीरे पर आयात शुल्क 5 से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत और सोने के गहनों पर 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने की स्थिति में हीरे का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। सोना पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत पर यथावत रहा है। कट-पालिश्ड हीरे पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने से पहले से ही कारोबार मंद चल रहा है। ऐसे में शुल्क बढ़ने पर हीरा जड़े गहनों का कारोबार 50-60 फीसद तक घटने की आशंका है।

नाइन डायमंड के एमडी संजय शाह के मुताबिक निर्यात किए गए हर 100 हीरों में से लगभग 5 फीसद खराब निकल जाते हैं, जिन्हें वापस मंगवाना पड़ता है। 5 फीसद खराब निकले हीरे की वापसी पर बढ़े शुल्क 2.5 प्रतिशत के आलावा जीएसटी मिलाकर 3 प्रतिशत अतिरिक्त चुकाना होगा। इस वजह से मुनाफा कम हो जाएगा।

दूसरी दिक्कत यह है कि भारत के छोटे कारखाना वाले अमेरिका, हांगकांग और जापान से ब्रोकन हीरे लाकर भावनगर, अहमदाबाद, सूरत में रिपेयरिंग करके 2.50-3 प्रतिशत मुनाफा कमाते थे, लेकिन यह मुनाफा डयूटी भरने में निकल जाएगा। हीरे के कारखाने बंद होते जा रहे हैं। पहले इन कारखाने में लगभग 20 लाख कारीगर काम करते थे, लेकिन फिलहाल उनकी संख्या घटकर 10 लाख से कम रह गई है।

घट रहा है मुनाफा: अब हीरा कारोबार में मुनाफा कम होता जा रहा है। फिलहाल लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का लोकल कारोबार है, उसके आधा हो जाने की आशंका है। मुंबई डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के कारोबारी सदस्य भरत वी. शाह ने बताया कि कट-पॉलिश्ड हीरे पर शुल्क बढ़ने से आयात घटेगा। फिलहाल हीरा आभूषण बाजार में कामकाज कम चल रहा है। इसके कारण उस पर और असर पड़ेगा।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत ने 14,607 करोड़ रुपए मूल्य के कट-पॉलिश्ड हीरे का आयात किया था। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में आयात 38 प्रतिशत घटकर 4,112 करोड़ रुपए रह गया। सोने के गहनों पर शुल्क बढ़ने से दिक्कत नहीं सोने के आयातित आभूषण पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घरेलू बाजार में आयातित आभूषण का हिस्सा बहुत कम है।

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक सोने के आयातित गहनों पर शुल्क 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में बनने वाले कुल आभूषण में उसका हिस्सा केवल 5 प्रतिशत है।